

प्रेषक,

जे०पी०जोशी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा होमगार्ड्स  
एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-5

देहरादून: दिनांक: 14 मार्च, 2008

विषय:-जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स श्रीनगर श्रीकोट में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या:- सीजी-2/होगा/2006/947 दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स श्रीनगर श्रीकोट में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत आगणन की आंकलित राशि सेन्टेज सहित रु० 136.45 लाख एवं बिना सेन्टेज के रु० 127.67 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि सेन्टेज सहित रु० 128.05 लाख एवं बिना सेन्टेज के रु० 119.81 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन देते हुए उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुपूरक मांग के माध्यम से उक्त प्रयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि में से रु० 24,00,000/- (रु० चौबीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) धनराशि आहरण करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय तथा निर्माण कार्य को भूमि/स्थल निर्माण प्रारम्भ करने हेतु हस्तातरण करा लिया जाय।
- (2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हों अथवा बाजार दरों पर ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा तदुपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
- (3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, प्राविधिक अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(2)

- (4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना मानकों के अनुसार स्वीकृत हो, स्वीकृत मानकों से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (5) एकमुश्त प्राविधान को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मानकों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) समस्त सामग्री को क्रय करने से पूर्व 'स्टोर पर्चेज नियमों' का अनुपालन तथा सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित कर ली जाय।
- (8) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में पूर्व भूमि व मिट्टी का परीक्षण कराकर भूमि मिट्टी पर निर्माण को भूगर्भ आदि बिन्दुओं से उपयुक्त होने की पुष्टि करा ली जाय।
- (9) निर्माण में भूकम्प रोधी तथा उर्जा संरक्षण डिजाइन/तकनीक/वास्तुकला का उपयोग किया जाय जिस हेतु निर्माण से पूर्व डिजाइन/तकनीक/वास्तुकला का विस्तृत आगणन व नक्शों में समावेश कर लिया जाय तथा निर्माण में पूर्व निर्माण पूर्ण होने पर इस संबंध में निर्माण इकाई से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय और संबंधित प्रमाण पत्र तथा अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाय।

2- उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के साथ होमगार्ड्स निदेशालय स्तर पर नियमानुसार विधीकृत संविदा (contract) करते हुए शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय। संविदा के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय :-

- (1) FUND FLOW कार्य की प्रगति के साथ जुड़ा रहेगा।
- (2) कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाय। सामान्य परिस्थितियों में नियत समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था पर अर्धदण्ड का प्राविधान रखा जाय।
- (3) वित्त विभाग द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित किये जाने के उपरान्त परियोजना की लागत में वृद्धि सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगी।
- (4) प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन की राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि, एक वर्ष अथवा मानसून जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए रोक ली जाय तथा यह अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि उपरोक्त के अतिरिक्त तभी अवमुक्त की जाय जब उपरोक्त कालावधि बीत जाय। यह धनराशि उपरोक्त के अतिरिक्त तभी अवमुक्त होगी जब महासमादेष्टा होमगार्ड्स की सहमति के अनुरूप "कार्य सन्तोषप्रद प्रमाण पत्र" होमगार्ड्स निदेशालय द्वारा निर्गत कर दिया गया हो।

3- जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाय।



- 4- जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0 13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम् 20 तारीख तक (पूर्व माह की सूचना) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 5- मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 6- शासन द्वारा परीक्षित आगणन (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।
- 7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-6 के "लेखाशीर्षक-2070-800-अन्य व्यय-01-कन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0102-होमगार्ड्स बल" हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन योजना मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1476/XXVII(5)/2007 दिनांक- 13मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/ (1)/XX(5)/08-75 होगा0/05 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मोहिनी रोड, देहरादून को परीक्षित आगणन की प्रति सहित।
- 5- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा सी.  
(एम0एस0चौहान)  
अनु-सचिव।